

संख्या काफी कम हो गई। कु-प्रबन्ध के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) केवल बिहार में अभ्रक खानों में काम करने वाले श्रमिक ही निधि की मेडीकल संस्थाओं में निःशुल्क इलाज के पात्र हैं। अभ्रक कारखानों में काम करने वाले श्रमिक इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(ग) से (ङ) इस समय, क्षेत्रीय अस्पताल तिसरी को आवासीय भवनों सहित बिहार सरकार को सौंपने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, क्षेत्रीय अस्पताल, तिसरी के निकट ही क्षय रोग खण्ड का भवन तथा क्षय रोग खण्ड के कुछ आवासीय क्वार्टर खाली पड़े हैं और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इन भवनों को उचित किराये पर अपने प्रयोग के लिए ले लें। अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

Misleading Claims about the Quality of Tyres

6062. SHRI R.P. SARANGI : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 307 on 14 December, 1983 regarding misleading claims about the quality of tyres and state :

(a) the steps taken to bring specific legislation to deal with deceptive and misleading advertisements by the trade and industry; and

(b) the specific recommendations or steps that are under consideration of Government ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGAN NATH KAUSHAL) : (a) and (b) The MRTTP (Amendment) Bill, 1983, now awaiting passage in

Parliament, proposes suitable amendments in the M.R.T.P. Act, 1969 so as to regulate certain well known unfair trade practices like false and misleading advertisements, bargain and switch selling, conducting promotional contests, hoarding and destruction of goods etc.

Amendment to Industrial Disputes Act

6063. SHRI SUNIL MAITRA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state when Government are going to introduce amendments to the Industrial Disputes Act to remove the legal loopholes that have enabled the employees to challenge in Court the provisions relating to the prevention of closures of industrial units ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : The section relating to closure has been redefined by the Industrial Disputes (Amendment) Act, 1982. The Act will come into effect from the date to be notified in the official Gazette.

मतदाताओं के लिए पहचान-पत्र

6064. श्री दयाराम शाक्य : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चुनावों में अनियमितताओं की समस्या तथा किए जाने वाले कदाचारों तथा कमजोर वर्गों के लोगों के नाम पर जाली मतदान करने को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं के लिए फोटोग्राफ सहित पहचान पत्रों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार को इस बारे में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?